

“मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता”—वेडेल फिलिप्स

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 23 मार्च 2025 रविवार

सम्पादकीय

हाशिये पर किसान

खेती—किसानी से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर किसानों के एक घटक द्वारा तेरह माह से चलाए जा रहे आंदोलन का बलपूर्वक समापन एक अच्छी स्थिति कदापि नहीं की जा सकती। हालांकि यह भी तय था कि यह आंदोलन अनिश्चितकाल के लिये नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन चंडीगढ़ में केंद्रीय मत्रियों की उपस्थिति में बात नवाने के बाद पंजाब सरकार की बलपूर्वकी गई कार्रवाई से धरना खल को खाली कराने पर किसान नेताओं की गिरफतारी से किसानों में रोष स्वाभाविक ही है। निर्विवाद

रूप से लंबे समय से खानीरी व शांति बॉर्डर से जुड़े राजमार्ग के बाधित होने से यात्रियों व कारोबारियों को भारी परेशानी का सम्पन्न करना पड़ रहा था। वहीं सरकार ने भी इस आवास पर अपनी कार्रवाई को बढ़ाव दिया बताया है कि दो प्रमुख राजमार्गों के लंबे समय तक बंद रखने से उद्योग और व्यवसाय दुरी तरह प्रभावित हो रहे थे। निजी वाहनों को भी लंबे रास्तों से सफर करने में अधिक समय व पटोल खर्च करना पड़ रहा था। वहीं किसान नेताओं का आरोप है कि उन्हें अंदोलन करने के उनके लोकतात्त्विक अधिकार से वचित करने का कदम दमनकारी है। जैसा

कि उम्मीद थी, विपक्षी राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर बयानबाजी शुरू कर दी है। लेकिन एक बात तो तय है कि किसान संगठन व सरकारें विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति बनाने में सफल नहीं हो पाए हैं। जिसके चलते राज्य सरकार व किसान संगठनों में अविश्वास व टकराव

बढ़ा है। विश्वनाथ यह भी है कि किसान संगठनों में मांगों को लेकर खासे मतभेद हैं। यदि सभी संगठन एमएसपी के मुद्दे पर एकजुट होकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाते तो शायद कोई सार्थक समाजान उन्नील पाता। लेकिन इसके परिपराण संगठन आपस में ही उलझते रहे। यही वजह है कि किसान संगठनों के घटते जनसमर्थन को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्त रुख जननाया। जबकि केंद्र सरकार भी इस मुद्दे के प्रति गंभीर नजर नहीं आयी।

जरूरी है कि केंद्र व राज्य सरकारें किसानों के मुद्दों पर

किंतु-परंतु की नीति को त्यागकर समयबद्ध तरीके से कृषि सकर्ता को दूर करने के लिये दृढ़ प्रतिवद्धता से बातचीत करें। विभिन्न मार्गों पर लौटीर रवैया दानों पर वो के लिये लाभकारी रहती हो सकता है। यह समय कि सान सगढ़नों के लिये भी आत्मसंरक्षण करें का है। उन्हें इन कृषि सुधारों के विरोध में वर्ष 2020-21 में फिल्टरों की सीमा पर चले लंबे कि सान आंदोलन के खराब संचालन से भी सबक लेना चाहिए। हालांकि, तीन प्रस्तावित कृषि कानून अंततः स्पष्टित कर दिए गए, लेकिन संकेतों कि सान सगढ़नों के लिये जिसका उद्देश्य विभिन्न कृषि कानूनों के विरोधी है, वह अभी तक नहीं किया जा रहा है।

अपनों जान भी गवानों पड़ो। इसके बावजूद फसलों का एमरस्पन हेतु कानून बनाने में विफलता ही हाथ लगी। निस्संदेह, लंबे किसान आदोलन से पंजाब के कारोबार को बहु पर निश्ची लगाया जा सकता था। लेकिन ध्यान रहे कि कृषि पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। ऐसे में सभी को साथ लेकर सुलह-सफाई करने के लिये गंभीर प्रयासों की जरूरत है। यदि ऐसा न होने पर राज्य में अशांति

बढ़ती है तो वित्तीय संकट से जूझते पंजाब को और मुश्किलों का सामना करना होगा। सरकार को भी धाटे का सौदा साबित हो रही खेती की दशा सुधारने के लिये

स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश का लागू करने का दिशा में सोचा चाहिए। वहीं कर्ज माफी की किसानों की मांग पर उदारतात्मक विचार करना चाहिए। जब उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया जाएगा तो सकता है कि तो किसानों का बद्यो नहीं। वहीं किसानों को भी चाहिए कि वे कृपी ऋण गैर उत्पादक कार्यों पर न खर्च करें। किसान संगठनों को भी एक मंच पर आकर जनता का विश्वास हासिल करना चाहिए, जो हाल में लगातार कम होता गया है। इस दिशा में केंद्र सरकार से भी गंभीर पहल की दरकार है। यह मुद्दा देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है। साथ ही उन मुद्दों को भी संवेदित करने की जरूरत है जो ज्ञालबल वर्षिंग के प्रभावों से पैदावार घटाने में भूमिका निभा रहे हैं। यह भी कि पंजाब में लगातार गिराव लूप्ट स्तर किसानों के सामने नये संकट पैदा कर रहा है। ऐसे में फसल विधिता के मुद्दे पर भी संवेदित करने की जरूरत है।

न्यायिक प्रक्रिया में सुधार समय की मांग

—ललित गग—

जल रखदान कर पढ़ाया दन के सकगं।

